© Eureka Journals 2024. All Rights Reserved. International Peer Reviewed Referred Journal

Anveshan: A Multidisciplinary Journal in Hindi
http://eurekajournals.com/Anveshan.html
ISSN: 2581-4044

विकासशील देशों में शैक्षिक संवर्धन के लिए वित्तपोषण का विश्लेषणात्मक अध्ययन

डॉ. अजय कृष्ण तिवारी[1]

[1]शिक्षाविद एवं अर्थशास्त्री और पीएच.डी. मार्गदर्शक।

सार

विकासशील देशों में उच्च शिक्षा के वित्तपोषण में पर्याप्त प्रगति हुई है, लेकिन कैसे? बजट में वृद्धि, संसाधनों में कमी उच्च शिक्षा पर घरेलू शिक्षा व्यय (डीआईई) उच्च शिक्षा के वित्तपोषण के लिए मुख्य संकेतकों में से एक है, यह केंद्र सरकार और राज्य सरकार, स्थानीय अधिकारियों, अन्य सार्वजनिक प्रशासन, घरेलू प्रशासन द्वारा उच्च शिक्षा पर व्यय है और व्यापार को एक साथ लाता है। यह उच्च शिक्षा वित्त पोषण की समग्र स्थिति का एक सिंहावलोकन प्रदान करता है। 1980 के दशक से उच्च शिक्षा के लिए वित्त पोषण लगभग लगातार बढ़ रहा है। उच्च शिक्षा के लिए प्रतिष्ठानों के व्यय की संरचना इस प्रकार है: व्यय का 42% शिक्षण कर्मचारियों के पारिश्रमिक के लिए, 30% गैर-शिक्षण कर्मचारियों के पारिश्रमिक के लिए, 19% संचालन के लिए और 8% निवेश के लिए आवंटित किया जाता है। [एमईएसआरआई, 2021]। हम ध्यान दे सकते हैं कि ओईसीडी [2021] द्वारा प्रकाशित सबसे हालिया आंकड़ों के अनुसार, सदस्य देशों ने 2018 में तृतीयक शिक्षा पर अपने सकल घरेलू उत्पाद का औसतन 1.4% खर्च किया। तृतीयक शिक्षा (सार्वजनिक और निजी) पर व्यय सकल घरेलू उत्पाद का 1.5% है। इस बात पर ज़ोर देना ज़रूरी है कि वे उच्च शिक्षा के वित्तपोषण की स्थिति पर केवल आंशिक जानकारी प्रदान करते हैं। दरअसल, कुल बजट में इस बढ़ोतरी के साथ-साथ छात्र संख्या भी तेजी से बढ़ रही है। शिक्षा के वित्तपोषण से संबंधित मौजूदा मुद्दों को समझने के लिए यह एक आवश्यक संकेतक है। उच्च शिक्षा में छात्रों को बजट में आनुपातिक वृद्धि से मुआवजा नहीं दिया जाता है।

कीवर्ड: वित्त पोषण, उच्च शिक्षा, बजट में वृद्धि, उच्च शिक्षा पर व्यय, छात्र संख्या, बजट में वृद्धि।

© Eureka Journals 2024. All Rights Reserved. International Peer Reviewed Referred Journal

परिचय

भारत में शिक्षा का प्रबंधन मुख्य रूप से राज्य द्वारा संचालित सार्वजनिक शिक्षा प्रणाली द्वारा किया जाता है, जो सरकार के तीन स्तरों के अधीन है: संघीय, राज्य और स्थानीय। भारतीय संविधान के विभिन्न अनुच्छेदों और बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 के तहत, यह मौलिक अधिकार छह से चौदह वर्ष की आयु के बच्चों पर लागू होता है। भारत में सार्वजनिक और निजी स्कूलों का अनुपात लगभग 7:5 है। भारत में शिक्षा के लिए कई सार्वजनिक पहल हो रही हैं। 1976 तक, शैक्षिक नीतियां और उनका कार्यान्वयन भारत में प्रत्येक संवैधानिक राज्य द्वारा कानूनी रूप से निर्धारित किया गया था। 1976 में संविधान में बयालीसवें संशोधन द्वारा शिक्षा को "समवर्ती विषय" बना दिया गया। इस प्रकार, 1976 से, केंद्र और राज्य सरकारों ने स्कूल के वित्तपोषण और प्रशासन के लिए औपचारिक जिम्मेदारी साझा की। अट्ठाईस राज्यों और आठ केंद्र शासित प्रदेशों वाले इस विशाल देश में शिक्षा नीति में कई विविधताएं हैं। राष्ट्रीय नीति ढाँचे राज्यों को उनके राज्य-स्तरीय कार्यक्रमों और नीतियों को तैयार करने में मार्गदर्शन करने के लिए बनाए जाते हैं।

प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों का संचालन

राज्य सरकारें और स्थानीय सरकारी एजेंसियां अधिकांश प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालयों का संचालन करती हैं, और सरकार द्वारा संचालित प्राथमिक विद्यालयों की संख्या बढ़ रही है। साथ ही, निजी संगठनों द्वारा प्रबंधित संख्या और अनुपात बढ़ रहा है। 2005 और 2006 में, प्रारंभिक शिक्षा (कक्षा 1 से 8) प्रदान करने वाले 83.13% स्कूल सरकार द्वारा चलाए गए थे और 16.86% स्कूल निजी प्रबंधन के अधीन थे (गैर-मान्यता प्राप्त स्कूल, शिक्षा गारंटी कार्यक्रम के तहत स्थापित स्कूल और बच्चों को छोड़कर वैकल्पिक शिक्षा सहित) अमेरिका में इन निजी स्कूलों में से एक-तिहाई को सार्वजनिक "सहायता" मिलती है। पहली और आठवीं कक्षा के बीच, सार्वजनिक और निजी स्कूलों के

© Eureka Journals 2024. All Rights Reserved. International Peer Reviewed Referred Journal

बीच नामांकन अनुपात 73:27 है। हालांकि, ग्रामीण क्षेत्रों में यह अनुपात अधिक है। (80का अनुपात20)। शहरी क्षेत्रों में यह कम है (36:66 का अनुपात)। 2011 में साक्षरता दर 73% है (पुरुष दर 81% और महिला दर 65% है)। राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग का अनुमान है कि 2017 में- 2018 में साक्षरता दर 77.7% होगी, जिसमें पुरुषों के लिए 84.7% और महिलाओं के लिए 70.3% होगी। हालाँकि, 1981 में, संबंधित दरें 41%, 53% और 29% थीं और 1951 में, दरें 18%, 27% और थीं 9%3. भारत की बेहतर शिक्षा प्रणाली को अक्सर इसके आर्थिक विकास में प्रमुख योगदानकर्ताओं में से एक के रूप में उद्धृत किया जाता है। प्रगति का एक महत्वपूर्ण हिस्सा, विशेषकर उच्च शिक्षा या अनुसंधान का, विभिन्न सार्वजनिक संस्थानों को जिम्मेदार ठहराया जाता है। है। 2010 के बाद से, उच्च शिक्षा में नामांकन बढ़कर 20195 में 26.3% की सकल नामांकन दर (जीईआर) तक पहुंच गया है। हालांकि, विकसित देशों की उच्च शिक्षा में नामांकन दर 6% तक पहुंचनेकी चुनौती है, इसे सक्षम करने के लिए इसे बढ़ाना होगा युवा भारतीय आबादी से जनसांख्यिकीय लाभांश प्राप्त करना।

प्राथमिक एवं माध्यमिक स्तर पर

सरकारी स्कूलों में संसाधनों की कमी और शिक्षकों की अनुपस्थिति निजी स्कूलों को बढ़ावा दे सकती है। इन्हें भारत सरकार द्वारा मान्यता दी जा सकती है। यह "मान्यता" अनुमोदन की एक आधिकारिक मुहर है जिसके लिए एक निजी स्कूल को कई शर्तों को पूरा करना पड़ता है (हालाँकि, व्यवहार में, मान्यता प्राप्त स्कूल सभी मानदंडों को पूरा नहीं करते हैं)। गैर-मान्यता प्राप्त प्राथमिक विद्यालयों के उद्भव से पता चलता है कि सरकारी मान्यता को स्कूलों और अभिभावकों द्वारा गुणवत्ता की गारंटी नहीं माना जाता है। प्राथमिक और माध्यमिक स्तर पर, भारत में एक व्यापक

© Eureka Journals 2024. All Rights Reserved. International Peer Reviewed Referred Journal

निजी स्कूल प्रणाली है जो सार्वजनिक स्कूलों की पूरक है, जिसमें 6 से 14 वर्ष की आयु के 29%छात्र निजी शिक्षा प्राप्त करते हैं। कुछ उच्च तकनीकी विद्यालय निजी भी हैं। भारत में निजी शिक्षा बाज़ार का कारोबार 2008 में 450 मिलियन अमेरिकी डॉलर का था, लेकिन इसके 40 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुँचनेकी उम्मीद है। 2012 की शिक्षा की वार्षिक स्थिति रिपोर्ट के अनुसार, 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी ग्रामीण बच्चों में से 96.5% ने उस वर्ष स्कूल में दाखिला लिया। यह वार्षिक सर्वेक्षण 96% से अधिक की नामांकन दर रिपोर्ट करने वाला चौथा है। 2007 से 2014 तक, भारत ने इस आयु वर्ग के छात्रों के लिए औसत नामांकन दर 95% बनाए रखी। परिणामस्वरूप, स्कूल में नामांकित नहीं होने वाले 6-14 आयु वर्ग के छात्रों की संख्या 2018 स्कूल वर्ष (एएसईआर 2018)9 में घटकर 2.8% हो गई। 2013 की एक रिपोर्ट के अनुसार, पूरे भारत में विभिन्न मान्यता प्राप्त शहरी और ग्रामीण स्कूलों में कक्षा 1 से 12 तक 229 मिलियन छात्र नामांकित हैं, 2002 में नामांकन की कुल संख्या से 2.3 मिलियन छात्रों की वृद्धि हुईहै, और 19% की वृद्धि हुईहै।

नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020

केंद्र सरकार द्वारा पेश की गई नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 भारत में शिक्षा में बदलाव लाने SSके लिए तैयार है। 29 जुलाई, 2020 को भारत के केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा अनुमोदित नीति, नई भारतीय शिक्षा प्रणाली के दृष्टिकोण को रेखांकित करती है। नई नीति 1986 की राष्ट्रीय शिक्षा नीति की जगह लेती है। यह नीति प्राथमिक से लेकर उच्च शिक्षा के साथ-साथ ग्रामीण और शहरी व्यावसायिक प्रशिक्षण के लिए एक वैश्विक ढांचा है।

इस परियोजना के प्रकाशन के तुरंत बाद, सरकार ने किसी विशेष भाषा का अध्ययन करने की बाध्यता की अनुपस्थिति को स्पष्ट किया। शिक्षण अंग्रेजी से क्षेत्रीय भाषाओं की ओर नहीं जाता है। एनईपी

© Eureka Journals 2024. All Rights Reserved. International Peer Reviewed Referred Journal

भाषा नीति प्रकृति में एक सामान्य निर्देश और सलाह है; और कार्यान्वयन पर निर्णय लेना राज्यों, संस्थानों और स्कूलों पर निर्भर है। भारत में शिक्षा समवर्ती सूची का विषय है।

इस प्रोग्राम के अनुसार, 10+2 संरचना को 5+3+3+4+2 मॉडल से बदल दिया गया है। ये संख्याएँ 5 मौलिक वर्षों को संदर्भित करती हैं, चाहे आंगनवाड़ी, प्रीस्कूल या किंडरगार्टन में हों। इसके बाद कक्षा 3 से 5 तक 3 साल की प्रारंभिक शिक्षा होती है। इसके बाद 3 साल का मध्यवर्ती चक्र और अंत में कक्षा 12 या 18 तक 4 साल का माध्यमिक चक्र होता है। इस मॉडल को निम्नानुसार लागू किया जाता है।

प्रत्येक स्कूल वर्ष में 1 परीक्षा के बजाय, छात्र ग्रेड 2, 5, और 8 में तीन परीक्षाएँ देते हैं। बोर्ड परीक्षाएँ कक्षा 10 और 12 के लिए आयोजित की जाती हैं। इन परीक्षाओं के मानक एक मूल्यांकन निकाय, PARAKH (प्रदर्शन मूल्यांकन, परीक्षा और) द्वारा निर्धारित किए जाते हैं। समग्र विकास के लिए ज्ञान का विश्लेषण)। इसे आसान बनाने के लिए, ये परीक्षाएं साल में दो बार आयोजित की जाती हैं, जिसमें छात्रों को दो प्रयासों तक की पेशकश की जाती है। परीक्षा को वस्तुनिष्ठ और वर्णनात्मक दो भागों में बांटा गया है।

उच्च शिक्षा नीति 26 व्यावसायिक आउटलेट्स के साथ बैचलर प्रोग्राम में 4-वर्षीय बहु-विषयक डिग्री प्रदान करती है:

- एक वर्ष की पढ़ाई पूरी करने पर प्रमाण पत्र
- दो साल की पढ़ाई के बाद डिप्लोमा

© Eureka Journals 2024. All Rights Reserved. International Peer Reviewed Referred Journal

- तीन साल का कार्यक्रम पूरा करने के बाद स्नातक की डिग्री
- चार वर्षीय बहु विषयक स्नातक डिग्री (पसंदीदा विकल्प)

प्रशासनिक नीति

निहोंगी ननथला इंग्लिश मीडियम स्कूल, मिज़ोरम की स्कूली लड़कियाँ शिक्षा नीति राष्ट्रीय स्तर पर केंद्र सरकार और राज्य स्तर पर राज्यों द्वारा तैयार की जाती है। 1986 की राष्ट्रीय शिक्षा नीति पर्यावरण जागरूकता, विज्ञान और प्रौद्योगिकी शिक्षा और योग जैसे पारंपरिक तत्वों को भारतीय माध्यमिक शिक्षा प्रणाली में एकीकृत करने का प्रयास करती है। भारत में माध्यमिक शिक्षा की एक पहचान व्यावसायिक प्रशिक्षण पर जोर देना है। एक महत्वपूर्ण विकास राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान के रूप में माध्यमिक शिक्षा के लिए समर्थन का विस्तार है, जो इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए भारत सरकार की सबसे हालिया पहल है। माध्यमिक शिक्षा का सार्वभौमीकरण. इसका लक्ष्य 10वीं कक्षा तक माध्यमिक शिक्षा के मानकों का विस्तार और सुधार करना है।

स्कूल बोर्ड

स्कूल बोर्ड पाठ्यक्रम लागू करते हैं, स्कूल डिप्लोमा प्रदान करने के लिए बोर्ड स्तर पर (विशेषकर स्तर दस और बारह पर) परीक्षा आयोजित करते हैं। ये ऐसे स्कूल हैं जो अन्य स्तरों (जिन्हें मानक, वर्ष या कक्षाएं भी कहा जाता है, जो स्कूली शिक्षा के वर्षों को दर्शाते हैं) के लिए परीक्षाएं आयोजित करते हैं।

राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद

यह भारत की राजधानी नई दिल्ली में स्थित सर्वोच्च निकाय है। यह पूरे भारत में स्कूली शिक्षा से संबंधित पाठ्यक्रम प्रदान करता है। यह भारत में स्कूलों को सहायता, सलाह और तकनीकी सहायता

© Eureka Journals 2024. All Rights Reserved. International Peer Reviewed Referred Journal

देता है और शिक्षा नीतियों के कार्यान्वयन के कई पहलुओं की देखरेख करता है। अन्य पाठ्यचर्या संबंधी निकाय हैं जो स्कूली शिक्षा प्रणाली को नियंत्रित करते हैं, विशेष रूप से राज्य स्तर पर।

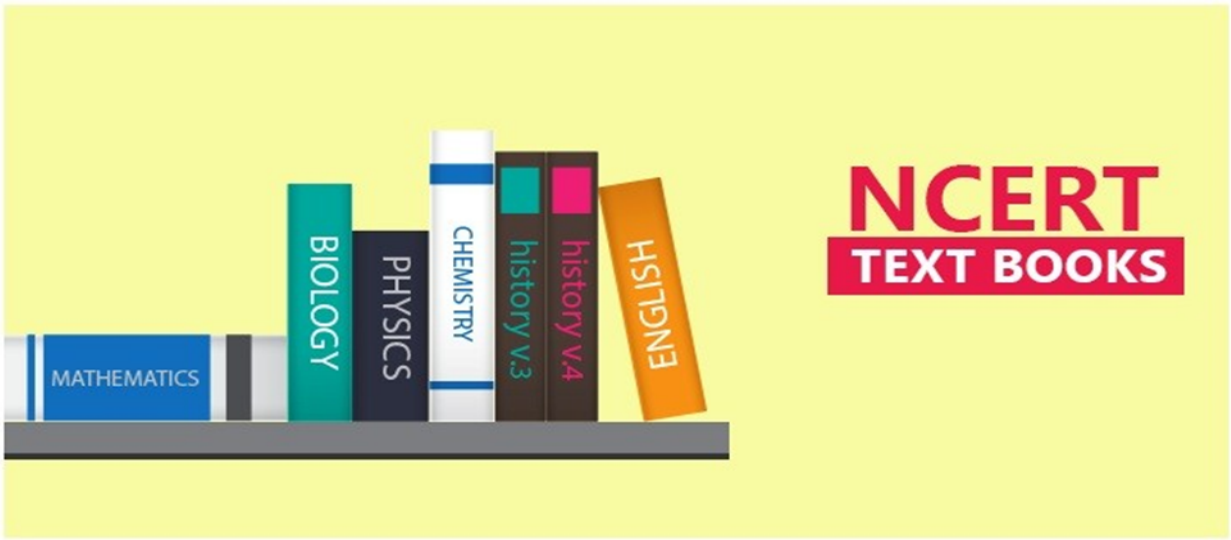

राज्य शिक्षा बोर्ड

अधिकांश राज्य सरकारों के पास कम से कम एक "राज्य माध्यमिक शिक्षा बोर्ड" है। हालाँकि, कुछ सेंटआंध्र प्रदेश जैसे राज्यों में कई हैं। इसके अलावा, केंद्र शासित प्रदेशों में कोई परिषद नहीं है। चंडीगढ़, दादरा और नगर हवेली, दमन और दीव, और लक्षद्वीप और पुडुचेरी लक्षद्वीप बड़े राज्य के साथ सेवाएं साझा करता है। स्कूल बोर्ड कक्षा 1 से 12 तक के कार्यक्रम के लिए पाठ्यक्रम निर्धारित करते हैं, जो राज्य के अनुसार अलग-अलग होता है। उनमें से अधिकांश 10वीं और 12वीं कक्षा में परीक्षा आयोजित करते हैं, लेकिन कुछ 5वीं, 6वीं और 8वीं कक्षा में भी परीक्षा आयोजित करते हैं।

केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड

यह कक्षा 1 से 12 तक के लिए पाठ्यक्रम निर्धारित करता है और कक्षा 10वीं और 12वीं में मानक परीक्षाएं आयोजित करता है जिन्हें बोर्ड परीक्षा कहा जाता है। स्कूल सीबीएसई पाठ्यक्रम का अध्ययन करने वाले छात्रों को परीक्षा देते हैं।

© Eureka Journals 2024. All Rights Reserved. International Peer Reviewed Referred Journal

केंद्र सरकार शिक्षा पर खर्च कर रही है

दसवीं पंचवर्षीय योजना (2002-2007) के तहत, भारत की केंद्र सरकार ने प्रारंभिक शिक्षा पर ₹288 बिलियन, अपने कुल शिक्षा बजट का 65.6%, माध्यमिक शिक्षा पर 9.9% या ₹43.25 बिलियन का व्यय निर्धारित किया है; वयस्क शिक्षा पर 2.9% या ₹12.5 बिलियन; उच्च शिक्षा पर 9.5% या ₹41.77 बिलियन; तकनीकी शिक्षा पर 10.7% या ₹47 बिलियन; और शेष 1.4% (₹624 बिलियन) विभिन्न शिक्षा कार्यक्रमों पर खर्च किया जा रहा है।

2011 और 2012 में, भारत की केंद्र सरकार ने भारत में प्राथमिक शिक्षा के लिए जिम्मेदार मुख्य विभाग, स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग के लिए 38,957 करोड़ रुपये आवंटित किए। इस आवंटन के भीतर, 21,000 करोड़ रुपये का अधिकांश हिस्सा प्रमुख कार्यक्रम "सेवा शिक्षा अभियान" के लिए आरक्षित है। हालाँकि, वर्ष 2011-2012 के लिए आधिकारिक तौर पर नियुक्त बोर्डिया समिति की 356.59 अरब रुपये की सिफारिश को देखते हुए 210,000 मिलियन रुपये का बजटीय आवंटन बहुत कम माना जाता है। यह उच्च आवंटन कानून "बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम", 2009 को लागू करने के लिए आवश्यक है। भारत में शिक्षा में सुधार के लिए, कई घोषणाएँ की गई हैं, उदाहरण के लिए यूनाइटेड प्रोग्रेसिव का राष्ट्रीय सामान्य न्यूनतम कार्यक्रम (एनसीएमपी)। . गठबंधन (यूपीए) सरकार. इन घोषणाओं के अनुसार, इनमें शामिल हैं: (ए) धीरे-धीरे शिक्षा व्यय को सकल घरेलू उत्पाद के लगभग 6% तक बढ़ाना। (बी) शिक्षा व्यय में इस वृद्धि का समर्थन करने और शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार करने के लिए, सभी केंद्रीय सरकारी करों के ऊपर एक शिक्षा कर लगाया जाएगा। (सी) सुनिश्चित करें कि कोई भी व्यक्ति आर्थिक पिछड़ेपन और गरीबी के कारण शिक्षा से वंचित न रहे। घ) 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों के लिए शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार बनाया जाना चाहिए। (ई) अपने प्रमुख प्रोग्रामरों के माध्यम से शिक्षा को सार्वभौमिक बनाना। हालाँकि, कार्यक्रम के कार्यान्वयन के पाँच वर्षों के बाद, बहुत कम प्रगति देखी गई है। हालाँकि देश ने शिक्षा क्षेत्र पर अपने सकल घरेलू उत्पाद का 6% खर्च करने का लक्ष्य रखा है, लेकिन प्रदर्शन उम्मीदों से कम रहा है। शिक्षा व्यय 1951-1952 में सकल घरेलू उत्पाद के 0.64% से बढ़कर

© Eureka Journals 2024. All Rights Reserved. International Peer Reviewed Referred Journal

1970-1971 में 2.31% हो गया और 2004-2005 में 3.49% तक गिरने से पहले 2000-2001 में 4.26% के शिखर पर पहुंचगया। कुल सार्वजनिक व्यय के अनुपात के रूप में, यह 2000-01 में लगभग 11.1% से बढ़कर यूपीए शासन के तहत लगभग 9.98% हो गया, हालांकि आदर्श रूप से इसे कुल बजट का लगभग 20% प्रतिनिधित्व करना चाहिए। [नेटवर्क फॉर सोशल अकाउंटेबिलिटी (एनएसए)] द्वारा प्रकाशित एक नीति संक्षिप्त शीर्षक जिसका शीर्षक है "[केंद्रीय बजट में शिक्षा क्षेत्र के हस्तक्षेप पर एनएसए प्रतिक्रिया: यूपीए नियम और शिक्षा क्षेत्र] इस तथ्य पर एक रहस्योद्घाटन प्रदान करता है। भारत में सार्वजनिक नीति अर्थव्यवस्था में शिक्षा को कम प्राथमिकता दिए जाने के कारण शिक्षा पर निजी खर्च तेजी से बढ़ रहा है। उपलब्ध जानकारी के अनुसार, भारत में श्रमिक वर्ग द्वारा अपने बच्चों की शिक्षा पर निजी खर्च 2010 से 2020 तक लगभग 11. 50 प्रतिशत या लगभग 12.5 गुना बढ़ गया है।

निष्कर्ष

यह मापना कि वास्तव में मानव पूंजी या कौशल क्या हैं? प्रत्येक देश के मानव संसाधनों की विशेषताएं, जो उनके विकास को सर्वोत्तम संभव बनाती हैं, एक आर्थिक चुनौती बनी हुईहैं, जिस पर मानव पूंजी का बेहतर व्यापक उपयोग करना हमारे लिए वास्तव में कठिन है। विकासशील देशों में शिक्षा का वित्तपोषण इस प्रक्रिया में सिर्फ एक कदम है। क्योंकि इस क्षेत्र में विश्लेषण और आर्थिक प्रतिबिंब. विकासशील देशों में शिक्षा प्रणालियों को आर्थिक और सामाजिक विकास को बढ़ावा देने के साथ-साथ व्यक्तियों और देशों को भी सक्षम बनाना चाहिए। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के हालिया प्रयासों के बावजूद, अधिकांश विकासशील देशों के पास बहुतकम पैसा है, इन देशों की मौद्रिक गरीबी के कारण,

© Eureka Journals 2024. All Rights Reserved. International Peer Reviewed Referred Journal

वित्तपोषण के मुख्य स्रोत राष्ट्रीय बजट (मुख्य रूप से राजकोषीय), कर आदि हैं। भारत और अन्य देश जो वर्तमान में हैं उभर रहा है. राष्ट्रीय शिक्षा प्रणाली के सामने वित्तीय चुनौती राज्यों की शिक्षा की गुणवत्ता में गिरावट की मजबूत प्रवृत्ति को उलटने की क्षमता में निहित है, जिसने सभी स्तरों पर प्रतिधारण को दंडित किया है। डेलोरिस (2004) के अनुसार, शिक्षा में एक खजाना छिपा है। अंतर्जात विकास प्रगति और नवाचार के लिए एक शर्त है। चाहे वह जापान हो, दक्षिण कोरिया हो, सिंगापुर हो या वर्तमान में चीन और भारत, उनका आर्थिक उद्भव प्रौद्योगिकी में महारत हासिल करने के महत्वपूर्ण प्रयासों से हुआ है। भारत और चीन में आईटी क्रांति चल रही है. जाहिर है, शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार की सख्त जरूरत है।

संदर्भ

एडनेट पी. (2019)। वित्त समिति की ओर से तैयार की गई सूचना रिपोर्ट-विश्वविद्यालय वित्त पोषण में प्रदर्शन, एन130। पीपी-21-29.

अनौक, आर., और हरारी-केर्मोड, एच. (2021)। फ्रांसीसी विश्वविद्यालय, मिश्रण या सामाजिक अलगाव का स्थान? फ्रांसीसी विश्वविद्यालय प्रणाली के ध्रुवीकरण को मापना (2007-2015), अर्थव्यवस्था और सांख्यिकी, 528(1), पीपी-63-84।.

उच्च शिक्षा पर अखिल भारतीय सर्वेक्षण 2018-19 [संग्रह] », उच्च शिक्षा विभाग (भारत) (17 जनवरी 2021 को एक्सेस किया गया) पीपी-32-47.

बेन्नानी, एच., बब्बागियन, जी. और पेरोन, एम. (2021)। "ट्रा की लागतफ्रांसीसी उच्च शिक्षा में प्रवेश: निर्धारक और असमानताएँ"। सीएई फोकस, संख्या 074-2021.पीपी-32-44.

ग्लोबल एजुकेशन, आर्काइव इ 8 दिसंबर 2015, यूनिवर्सिटी एनालिटिक्स (10 दिसंबर 2015 को एक्सेस किया गया) पीपी. 21-43.

किंग्टन ई.एन., 2007, द प्रोग्रेस ऑफ स्कूलिंग इन इंडिया », ऑक्सफोर्ड रिव्यू ऑफ इकोनॉमिक पॉलिसी, वॉल्यूम। 23, संख्या 2, 1 जून 2007, पृ. 168-195.

भारतीय शिक्षा: सेक्टर आउटलुक ASER-2018 संग्रहीत 24 सितंबर 2015, परामर्श 23 जनवरी 2014) पीपी-42-61.

रजनी पार्थेनिया, 2008 "भारत में साक्षरता: प्रगति और असमानता।" भारत ने गरीबी में 27% की गिरावट हासिल की, प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया Sify.com के माध्यम से, पृष्ठ 56-63.